



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 499]  
No. 499]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, नवम्बर 10, 1983/कार्तिक 19, 1905  
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 1983/KARTIKA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेद

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1983

का० आ० 801(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 641(अ), तारीख 10 नवम्बर, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) बैन्ट बंगाल फार्मास्यूटिकल एण्ड फिटोकेमिकल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, इलाको हाऊस (दूसरी मंजिल) 1 और 3, बार्बोर्न रोड, कलकत्ता-700001 को (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स डा० पाल लोहमान (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध 10 नवम्बर, 1978 में प्रारम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 793(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1981, सं० का० आ० 312(अ), तारीख 8 मई, 1982 और का० आ० 789(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय की अनुज्ञा से, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 9 नवम्बर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, पांच वर्ष की अवधि के लिए करते रहने के लिए समय-समय पर निर्देश दिया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने, अपनी यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित में यह समीचीन था कि उक्त प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी करती रहे, उक्त अधिनियम की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था

और उसमें ऐसे प्रबन्ध को छह मास की और अवधि के लिए बनाए रखने के लिए प्रार्थना की थी;

और, उक्त उच्च न्यायालय ने, अपने आदेश तारीख 8 नवम्बर, 1983 द्वारा, उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध छह मास की और अवधि के लिए करते रहने की अनुज्ञा दे दी थी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 18(क) की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 10 नवम्बर, 1983 से ही छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 4(2)/80-सी० यू० एस०]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

#### MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 10th November, 1983

**S.O. 801(E)** :—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No.S.O. 641(E), dated the 10th November, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government had authorised the West Bengal Pharmaceutical and Phytochemical Development Corporation Limited, Ilaco House (2nd floor), 1 and 3, Barbourne Road, Calcutta-700001, (hereinafter referred to as the said authorised person), to take

over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Dr. Paul Lohmann (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), for a period of three years commencing on the 10th November, 1978;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O.793(E), dated the 9th November, 1981, S.O. 312

(E) dated the 8th May, 1982 and S. O. 789(E), dated the 9th November, 1982, the Central Government, with the permission of the High Court at Calcutta, under section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, had from time to time directed the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a period of five year upto and inclusive of the 9th November, 1983;

And, whereas, the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of the general public that the said authorised person should continue to manage the said industrial undertaking after the expiry of the said period of five years, made an application under the proviso to sub-section (2) of Section 18FA of the said Act, to the High Court at Calcutta praying for the continuance of such management for a further period of six months;

And, whereas, the said High Court, by its Order dated the 8th November, 1983, permitted the said authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the said Act, the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months, on and from the 10th November, 1983.

[F.No. 4(2)/80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.